

## नीति-निरिधारकों के लिये सचेत होने का समय

### चर्चा में क्यों ?

वर्ष 2013 के बाद से भारत के बाह्य संतुलन खाते में महत्त्वपूर्ण सुधार हुआ है, परन्तु इसमें अब भी कुछ ऐसे चिन्ह मौजूद हैं जो नीति-निरिमाताओं से और सावधानी बरतने की उम्मीद करते हैं। पछिले सप्ताह देश का चालू खाता घाटा (current account deficit) चालू वित्त वर्ष के प्रथम त्रिमाही में बढ़ कर \$14.3 अरब हो गया जो पछिले चार वर्ष के उच्च स्तर पर है। यह जीडीपी का 2.4% हो गया है जो पछिले वर्ष 0.1% ही था।

### प्रमुख बिंदु

- देश के चालू खाता घाटा के बढ़ने का कारण निर्यात की तुलना में आयात का अधिक होना है। हालाँकि, पूंजीगत खाता अधिशेष के मज़बूत होने के कारण देश अपने आयात बलि का बर्तन किसी समस्या के भुगतान करने में सक्षम रहा है।
- भारत अब भी वदेशी निवेशकों के लिये आकर्षक गंतव्य बना हुआ है। पछिले साल की तुलना में इस वर्ष के प्रथम त्रिमाही में प्रत्यक्ष वदेशी निवेश दुगुना होकर \$7.2 अरब हो गया है। इस दौरान शुद्ध पोर्टफोलियो निवेश भी 12.5 अरब डॉलर रहा।
- वदेशी पूंजी के मज़बूत प्रवाह के कारण वदेशी रज़िर्व होल्डिंग्स में भी महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
- 8 सितंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत का वदेशी मुद्रा भंडार 400.7 अरब डॉलर के उच्चतम स्तर पर था।
- पछिले दो वर्षों में वैश्विक तेल की कीमतों में कमी के कारण आयात बलि कम रहा।
- हालाँकि ये परिस्थितियाँ अमेरिकी फ़ेडरल रज़िर्व (U.S. Federal Reserve) एवं अन्य केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति को सख्त करने के साथ बदल सकती हैं। आखिरकार उभरते हुए एशियाई बाज़ार पश्चिमी देशों में ढीले मौद्रिक नीति के सबसे बड़े लाभार्थी रहे हैं, इसलिए उनके रुख में कोई भी बदलाव इन्हें नश्वरि रूप से प्रभावित करेगा।
- भारतीय कंपनियाँ रुपए के वरचस्व वाले वदेशी करज़ फंस गई हैं और वदेशी पूंजी के अस्थिर होने की स्थिति में संकट में पड़ जाती हैं।
- आरबीआई ऐसे उधारों की मात्रा और गुणवत्ता को वनियमि करता है अतः यह ऐसा प्रतीत हो सकता है कि चीजें उसके नियंत्रण में हैं।
- बाहरी वाणज्यिक उधारों में गरिवट एवं अनवासी भारतीयों द्वारा जमा किये जाने के कारण भारत का कुल बाह्य ऋण वित्त वर्ष 2016-17 में 2.7% तक घटकर \$471.9 अरब पर आ गया।
- वश्व बैंक ने भी कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था के आकार और वदेशी रज़िर्व होल्डिंग्स के कारण भारत का बाह्य गतशीलता बहुत ही अनुकूल है। परन्तु प्रतकूल व्यापार संतुलन की लंबी अवधि अस्थिर अंतरराष्ट्रीय पूंजी बहाव से जुड़कर बेपरवाह व्यापक आर्थिक स्थितियों की ओर जा सकती है।
- भारत रेटगिंस और रसिर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, रुपए की 10% अवमूल्यन एवं 50 आधार अंकों की ब्याज दरों में वृद्धि संयुक्त रूप से अनेक भारतीय उधारकर्त्ताओं को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है।
- जैसा कि वश्व ऐतहासिक रूप से कम ब्याज दरों के युग से पीछे हटने लगा है, भारतीय नीति-निरिमाताओं के लिये यह समझदारी यह होगी कि वे महत्त्वपूर्ण अस्थिरता की अवधि से नपिटने के लिये एक आपात योजना तैयार रखें।